

**सं. 402/92/2006-एमसी (2007 का 14)**  
**भारत सरकार/वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग**  
**केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड**  
\*\*\*

नई दिल्ली दिनांक 19th अप्रैल, 2007

**प्रेस विज्ञप्ति**

मीडिया के कुछ वर्गों में यह खबर आई है कि बड़ी संख्या में करदाता, तीन साल तक से आयकर विभाग के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और तथ्यों के अधूरे मूल्यांकन पर आधारित हैं।

आयकर विभाग वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान 39,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के 43 लाख से अधिक रिफंड चेक पहले ही जारी कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान जारी रिफंड की राशि 29,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस प्रकार 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान जारी किए गए रिफंड की राशि में लगभग 33% की वृद्धि हुई है। केवल अप्रैल 2007 के पहले दो सप्ताहों में 1,834 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड जारी किया गया है।

रिफंड के मुद्दे में तेजी लाने और प्रक्रिया को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए, वित्त मंत्री द्वारा 24 जनवरी 2007 को दिल्ली और पटना में चुनिंदा आयुक्तालयों में एक पायलट रिफंड बैंकर योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, दिल्ली और पटना में ईसीएस के माध्यम से या पेपर रिफंड के रूप में 30,000 से अधिक रिफंड जारी किए गए हैं। ज्यादातर मामलों में, रिफंड करदाताओं तक पहुंच गया है या प्रसंस्करण के 15 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके बैंक खाते में जमा कर दिया गया है।

कर विवरणी के प्रसंस्करण में समय लगता है। आयकर विभाग को 3.20 करोड़ से अधिक कर विवरणी प्राप्त होती हैं। प्रशासनिक रूप से, विवरणी का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण पूरा करने में 4 महीने का समय लगता है। कभी-कभी जनशक्ति की कमी, कनेक्टिविटी, बिजली की विफलता आदि के कारण देरी होती है। इन मुद्दों का अलग से समाधान किया जा रहा है।

कर विवरणी संसाधित करते समय, यह देखा गया है कि कई करदाता सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। बैंक खाता विवरण या ईसीएस कोड प्रस्तुत नहीं किया गया है या गलत/अधूरा है। कभी-कभी करदाताओं के पते बदल जाते हैं और इसकी कोई सूचना विभाग को नहीं दी जाती है। इन कारकों की वजह से भी रिफंड में देरी होती है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कर विवरणी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ दाखिल करें।

छोटे और मध्यम करदाताओं को अपनी विवरणी दाखिल करने में मदद के लिए एक कर विवरणी तैयारकर्ता योजना भी शुरू की गई है।